Digital literacy under PMGDISHA

*63. SHRI AMAR SHANKAR SABLE: Will the Minister of ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY be pleased to state:

(a) the total population made digitally literate under the Pradhan Mantri Gramin Digital Shaksharta Abhiyan (PMGDISHA) *vis-a-vis* target fixed for the purpose during the last three years, year-wise, specially in Maharashtra:

(b) the reasons for very slow pace of implementation of the scheme; and

(c) the fresh steps taken by Government for proper implementation of the scheme particularly in remote rural areas?

THE MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Under the Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan (PMGDISHA), as on 24th June 2019, more than 2.30 crore beneficiaries have been enrolled and around 2.22 crore have been trained, out of which more than 1.34 crore have been duly certified by duly authorized 3rd party Certifying Agencies. The State-wise/UT-wise targets set under the scheme and the year-wise since FY 2017-18 regarding number of beneficiaries trained and certified are given at Annexure (*See* below). As against a target of 44.33 lakh beneficiaries to be covered for the state of Maharashtra, 9.4 lakh rural citizens have been trained so far, out of which 7 lakh have been duly certified.

(b) Some of the challenges faced in implementation of the scheme include:

- Low internet connectivity in some of the very remote rural areas
- Need for greater awareness about benefits of digital literacy
- Difficulty in covering non-accessible and sparsely populated areas
- Infrastructure related issues.

(c) Government has taken up several steps for proper implementation of the scheme particularly in remote rural areas of the country which include:

- Scaling up the awareness and promotional activities towards Digital literacy program and expand it multifold through campaigns, workshops, seminars, digital vans, etc.
- Efforts have been made to identify and register new Training centres in uncovered Gram Panchayats across the country.
- In order to address the low internet connectivity issues, Wifi-choupals have been established at remote locations.
- Rural schools have been engaged for training and examination of candidates in order to penetrate the rural populous districts of identified states.

Annexure

The State-wise/UT-wise targets set under PMGDISHA and the year-wise since FY 2017-18 regarding the no. of beneficiaries trained and certified

Sl. No.	State	Targets (no. of beneficiaries)	Achievement Status (no. of beneficiaries)					
			FY 2017-18		FY 2018-19		FY 2019-20	
			Trained	Certified	Trained	Certified	Trained	Certified
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Andhra Pradesh	20,28,000	2,18,761	1,18,893	3,01,045	1,42,034	12,625	6,504
2	Arunachal Pradesh	77,000	381	70	1,848	465	47	33
3	Assam	19,29,000	89,788	12,929	9,88,724	6,40,771	86,177	1,12,574
4	Bihar	66,30,000	7,95,999	4,09,886	7,57,427	4,94,820	72,532	64,573
5	Chhattisgarh	14,12,000	7,13,563	3,58,546	6,18,543	4,59,752	55,909	44,484
6	Goa	40,000	3	-	181	2	5	59
7	Gujarat	24,97,000	7,56,670	4,16,867	3,97,698	2,89,883	22,984	27,385
8	Haryana	11,91,000	6,78,104	3,83,619	3,93,341	2,68,983	56,082	49,246
9	Himachal Pradesh	4,44,000	81,968	32,343	36,393	21,685	6,761	5,218
10	Jammu and Kashmir	6,58,000	1,40,398	74,203	96,984	71,505	20,833	12,937
11	Jharkhand	18,03,000	9,68,471	4,77,010	2,93,011	2,18,031	31,525	29,047

12	Karnataka	27,05,000	3,14,184	1,72,607	1,67,506	1,03,146	6,297	5,289
13	Kerala	12,57,000	12,406	4,095	9,638	4,194	1,280	900
14	Madhya Pradesh	37,84,000	7,58,857	3,64,122	7,71,886	5,13,283	78,380	75,653
15	Maharashtra	44,33,000	4,22,138	2,83,065	4,28,508	3,57,473	90,174	59,525
16	Manipur	1,37,000	6,126	1,766	1,755	910	300	59
17	Meghalaya	1,71,000	507	3	42,986	15,386	8,744	7,909
18	Mizoram	38,000	4,387	2,254	834	212	67	29
19	Nagaland	1,01,000	1,173	773	1,459	633	474	261
20	Odisha	25,17,000	7,72,041	4,14,710	5,56,118	3,38,211	43,069	36,809
21	Punjab	12,47,000	2,73,886	1,61,814	4,38,969	3,14,444	35,043	26,968
22	Rajasthan	37,12,000	7,21,780	3,57,402	4,91,318	3,39,133	55,122	42,880
23	Sikkim	33,000	-	-	39	3	2	0
24	Tamil Nadu	26,79,000	3,50,604	1,98,848	1,71,365	1,09,509	9,033	7,067
25	Telangana	20,28,000	2,18,540	1,16,069	1,47,465	98,518	15,308	10,412
26	Tripura	1,95,000	32,612	17,844	38,196	17,724	4,239	2,918
27	Uttarakhand	5,06,000	1,62,127	93,431	95,647	65,474	12,283	10,563
28	Uttar Pradesh	1,11,71,000	24,73,387	12,31,890	24,22,173	16,28,818	2,75,449	2,35,312
29	West Bengal	44,81,000	3,17,367	1,41,971	1,98,484	1,46,421	28,278	18,637
30	Union Territories	96,000	6,444	2,661	4,815	2,365	299	202
	Total	6,00,00,000	1,12,92,672	58,49,691	98,74,356	66,63,788	10,29,321	8,93,453

श्री अमर शंकर साबले: महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं, डिजिटल इंडिया और प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षतर अभियान के अंतर्गत देश और विशेष तौर पर महाराष्ट्र के कितने गांवों में leasead line network पहुंचा है? जिन गांवों में यह leased line network पहुंचा हुआ है, उन गांवों के स्कूलों तक भी leased line network पहुंचाने की क्या सरकार की कोई योजना है, ताकि डिजिटल साक्षता अभियान गतिमान हो सके?

श्री रवि शंकर प्रसाद: माननीय उपसभापति जी, डिजिडल इंडिया एक समावेशी भारत की कल्पना करता है, ताकि तकनीकी के माध्यम से भारत का आम नागरिक अपने दिन भर के जीवन-यापन में शक्ति प्राप्त कर सके। डिजिटल इंडिया कई स्वरूपों में कार्य करता है। इससे हमारे पास एक विचार यह आया कि जब तक हम उनको डिजिटली साक्षर नहीं करेंगे, तब तक वे डिजिटल उपकरणों के साथ काम नहीं कर पाएंगे। इसके तीन स्तर थे। पहले स्तर में हमने 10 लाख लोगों को पायलेट में train किया, दूसरे स्तर में हम लोगों ने लगभग 53 लाख लोगों को train किया और फिर इसका विस्तारीकरण 'पीएमजीदिशा' में किया। इसमें हम देश के छ: करोड़ ग्रामीण लोगों को डिजिटली साक्षर करने का कार्यक्रम बना रहे हैं, जिनमें से 2.32 करोड़ हो गए हैं।

महोदय, मैं इसमें सिर्फ एक बात बताना चाहूंगा कि किस प्रकार हमारा भारत समावेशी भारत बन रहा है। महाराष्ट्र के संबंध में हमारे पास जो आंकड़े हैं, उनके अनुसार इसमें जो लोग रजिस्टर हुए, उनमें 5 लाख, 64 हजार महिलाएं थीं और 6 लाख 15 हजार पुरुष थे। जो ट्रेंड हुए, उनमें 4 लाख, 42 हजार महिलाएं थीं और 5 लाख पुरुष थे। यह साक्षरता एक प्रकार से हमें समावेशी भारत की ओर बढ़ा रही है, यह संतोष की बात है।

श्री अमर शंकर साबले: माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है कि भारत डिजिटल साक्षरत की ओर गतिमान हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि जो समावेशी भारत है, उसमें एससी, एसटी और बीपीएल के कितने लोग साक्षर हुए हैं और इस दिशा में सरकार कौन सा कदम उठाने वाली है?

श्री रवि शंकर प्रसाद: माननीय उपसभापति जी, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, मैं सदन को इस बारे में बताना चाहता हूं कि पिछले पांच साल से मैं आईटी विभाग को देख रहा हूं और मेरी सदैव यही कोशिश होती है कि समावेशी डिजिटल भारत प्रोग्राम तब तक सफल नहीं होगा, जब तक इसमें वंचित समाज के लोग नहीं आएंगे। इनकी इंग्ज़ैक्ट संख्या कितनी है, अभी मेरे पास उसके आंकड़े उपलब्ध नहीं है, लेकिन मैं आपको ये आंकड़े दे दूंगा। मैं सदन को एक बात बताना चाहता हूं कि Common Service Centre, देश भर में एक डिजिटल खिड़की है, जिसकी संख्या लगभग 80 हजार थी, लेकिन अब तक हम उसकी संख्या को बढ़ाकर 3.5 लाख तक ले गए हैं। इनमें से लगभग 2 लाख, 35 हजार सेंटर्स ग्राम पंचायतों में हैं, जिनमें 12 लाख बच्चे-बच्चियां काम करते हैं। उन्होंने लगभग 70,000 करोड़ रुपये का ट्रांज़ैक्शन किया है, पैन कार्ड और आधार कार्ड के माध्यम से। इनमें कई बेटियां वंचित समाज से हैं, जिन्हें मैं जानता हूं। जब हम उनको लेकर चलेंगे, तभी समवेशी भारत बन पाएग।

SHRI SUBHASISH CHAKRABORTY: Mr. Deputy Chairman, Sir, through you, I would like to know whether it is true that the Pradhan Mantri Gramin Digital Shaksharta Abhiyan

(PMGDISHA) has been hit by widespread fraud where village level entrepreneurs, who are there to impart basic computer skills under this scheme, have faked the number of people they have trained. If so, what are the details thereof, and, what is the Government doing to ensure that the number of beneficiaries under this scheme is not inflated.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, it is a very, very important scheme. There is a third-party audit. Third-party examinations are conducted by C-DAC and many bodies. If the hon. Member has any specific information of faking the number, I want to assure him that I will take very firm measures. But I know for sure that it has become a kind of movement and therefore we propose to scale it further along with digital villages because we really want to empower ordinary Indians. Therefore, if anyone has faked the numbers, I want to assure you that I would take very tough measures.

श्री महेश पोद्दार: उपसभापति महोदय, हमारी सरकार digital literacy को सुदूर क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए काफी काम कर रही है और उधर भारतीय रेल ने अपनी सारे रेलवे स्टेशंस पर free Wi-Fi की सुविधा देने का लक्ष्य रखा है तथा उस पर काम चल भी रहा है। तो क्या मैं उपेक्षा करूं कि ये दोनों मंत्रालय मिल-जुल कर काम करेंगे, ताकि उन जगहों पर, जहाँ यह सुविधा नहीं है, वहाँ इस सुविधा का पूरा लाभ हम ले सकें और सुदूर क्षेत्रों के लोग भी इसका फायदा जल्दी उठा सकें?

श्री रवि शंकर प्रसाद: माननीय उपसभापति जी, इस प्रश्न का digital literacy के प्रश्न से कोई सीधा नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि उन्होंने यह प्रश्न किया है, तो मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि रेल विभाग और मेरा संचार विभाग मिल कर optical fiber network ग्राम पंचायत में पहुंचे, इसका हम पूरा काम कर रहे हैं। हम देश में 1 लाख digital villages बनाने जा रहे हैं, जहाँ पर हम Wi-Fi की सुविधा देंगे तथा अन्य बाकी काम करेंगे। तो साथ मिल कर काम करने की काफी संभावना है। इसको और तेज़ किया जाए, क्योंकि उपसभापति जी, मैं एक बात बड़ी विनम्रता से बताना चाहूंगा कि देश में, विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में जो डिजिटल भूख जगी है, वह बदले हुए भारत का एक बहुत बड़ा संकेत है। तो उस भूख को हम और आगे बढ़ाएँ, यह हमारी कोशिश होगी।

*64 [*The questioner was absent.*]

Progress of Chandrayaan-2 mission

*64. DR. T. SUBBARAMI REDDY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the details of progress of Chandrayaan-2 mission;

(b) when the mission would take-off for the journey;

(c) the manoeuvers worked out for soft landing of the spacecraft on the moon; and